

an>

Title: Regarding alleged scam of Rs. 12,000 crore in wheat procurement in Punjab.

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर) : अध्यक्ष महोदया, मैंने कल इसी विषय पर एडजर्नमेंट मोशन का भी नोटिस दिया था। आपका धन्यवाद कि आपने आज मुझे इस पर विषय पर बोलने का समय दिया है। मैडम, पंजाब कृषि प्रधान प्रांत है और देश के अन्न भंडार में सबसे ज्यादा हिस्सा पंजाब डालता है। पंजाब में अब गेहूं की जो फसल है, एक अप्रैल से उसकी प्रोक्योरमेंट शुरू हुई है। आज तक 84.79 लाख मीट्रिक टन का अराइवल मंडियों में है। मेरे अपने संसदीय क्षेत्र जालंधर में 3.89 मीट्रिक टन है। मैं यहां आने से पहले अपने क्षेत्र की मंडियों का दौरा कर के आया हूँ। मैंने वहां देखा कि एक अप्रैल से ले कर दो दिन तक वहां कोई लिफ्टिंग नहीं हो रही है, उन किसानों की पैमेंट नहीं हो रही है। मैडम, अप्रैल के पहले सप्ताह में पंजाब सरकार ने आरबीआई को कैंश क्रेडिट लिमिट के लिए 21 हजार करोड़ रुपये के लिए कहा था। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि आरबीआई ने कहा कि आपका जो स्टॉक है, उसमें 12 हजार करोड़ रुपये का जो गेहूं है, वह मिसिंग है। मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत बड़ा स्कैम है और मेरे प्रांत पंजाब की सरकार की जो फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी है, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पंजाब में शिरोमणी अकाती दल की जो सरकार है, यह लगातार सेंट्रल फंड्स चाहे वह कैंश क्रेडिट लिमिट है, या दूसरी हैं, उनको डायवर्ट कर के ये दूसरे कामों के लिए, चाहे वह संगत दर्शन है, आदि ऐसे कामों के लिए यह यूज करती है। मैडम, पंजाब के फूड मिनिस्टर का यह स्टेटमेंट है कि मैंने 800 करोड़ रुपये दूसरे कामों के लिए जैसे आटा दाल स्कीम के लिए खर्च किया है।

महोदया, मेरा यह अनुरोध है कि यह एक बड़ा स्कैम है और मैंने प्रधान मंत्री साहब को विद्दी भी लिखी है, होम मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, फूड मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसकी सीबीआई इंवायरी हो। मंत्री जी, पासवान साहब इधर बैठे हैं, यह जो बड़ा धब्बा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऊपर लगा है, वह सामने आए कि क्या वजह है, किसने यह किया है, मंत्री जी यहाँ बैठे हैं।

माननीय अध्यक्ष : विष्णु दयाल राम जी आप बोलिए।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : हम लोग उसे देख रहे हैं और वह हो जाएगा।